

...2...

4- श्रीमति मनोरमा बाई पुत्री रामधन अग्रवाल
पतिन ओमप्रकाशजी अग्रवाल सराफ निवासी सराफा
चौक भोपाल जिला भोपाल

5- श्रीमति सुन्नीबाई उर्फ स्नेहलताबाई पुत्री रामधन
अग्रवाल पतिन विसोद कुमार अग्रवाल निवासी
सो/54 एन० आर्डी० जी० खंडवा जिला खंडवा ४००१०१

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 में प्र०क्र० रा० सं०.

उपरोक्त पुनरीक्षण कर्ता/ आवेदिका न्यायालय
श्रीमान तहसीलादर महोदय उरदा द्वारा रा० प्र०क्र० 27 अ/

2012-13 में पारित आदेश दिनांक 8-5-14 से व्यथित भुक्त होकर
निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुतकी जा
रही है।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर


प्रकरण क्रमांक - निग0 1539-पीबीआर/14 [चिंतावाही/सम्बन्धी]


जिला - हरदा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11.6.2014	<p>आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। तहसीलदार के आदेश दिनांक 8.5.2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में दिनांक 28.4.2014 को तहसीलदार द्वारा स्वत्व सम्बन्धी निराकरण के लिये समय नहीं दिया गया था एवं प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया था, परंतु दिनांक 8.5.2014 अनावेदकगण के आवेदन पत्र पर स्वत्व के निराकरण हेतु 90 दिवस के लिये कार्यवाही स्थगित करने में अवैधानिकता की गई है। उनके द्वारा निगरानी ग्राह्य किये जाने का अनुरोध किया गया। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178 में स्वत्व का प्रश्न उठाये जाने पर 90 दिवस के लिये कार्यवाही स्थगित किये जाने का प्रावधान है। अतः तहसीलदार द्वारा स्वत्व का प्रश्न उठाये जाने पर 90 दिवस के लिये कार्यवाही स्थगित करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है। इस सम्बन्ध में आवेदिका के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि पूर्व में तहसीलदार द्वारा स्वत्व के निराकरण के लिये समय नहीं दिया गया था, परंतु बाद में 90 दिवस के लिये कार्यवाही स्थगित करने में अवैधानिकता की गई है, क्योंकि यदि पूर्व में तहसीलदार द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत कोई कार्यवाही कर दी गई है, तो बाद में विधि के प्रावधानों के अनुरूप की</p>	

गई कार्यवाही को त्रुटिपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता है ।

2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।


(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष


11/6